

## वकिलांगता को समाप्त करना

यह एडिटरियल 08/11/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "On disabled persons, Supreme Court gives a welcome order with problematic observations" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में दवियांगजनों से संबंधित मुद्दों और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के रुख के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ:

भारत का संवधान दवियांगजनों सहित सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरमा सुनिश्चित करता है तथा सभी के लिये एक समावेशी समाज को अनविरय करता है। हालाँकि, दवियांगता को मापना एक जटिल परिघटना है क्योंकि अलग-अलग दृष्टिकोणों के कारण अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दवियांगता की परिभाषाएँ व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं।

भारत [दवियांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय \(Convention on the Rights of Persons with Disabilities\)](#) का हस्ताक्षरकर्ता है। हालाँकि वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों द्वारा 44% संकेतकों का पालन नहीं किया जाता है।

इसे भारत के संदर्भ में देखें तो न्याय तक पहुँच और समावेशी होने का अधिकार एक चुनौती है क्योंकि भारत में 'दवियांग' के रूप में वर्गीकृत होने के लिये कठोर शर्तें आरोपित हैं, जिनमें संबोधित किये जाने की आवश्यकता है।

### संयुक्त राष्ट्र दवियांगता को कैसे देखता है?

- [संयुक्त राष्ट्र](#) द्वारा अंगीकृत दवियांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय (CRPD), 2006 की प्रस्तावना में दवियांगता को इस रूप में वर्णित किया गया है:
  - "दवियांगता दवियांगजनों और व्यवहारगत एवं पर्यावरणीय बाधाओं के बीच अंतःक्रिया उत्पन्न होती है जो अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी को अवरुद्ध करती है।"
- संयुक्त राष्ट्र की यह अभिव्यक्ति दवियांगता के चिकित्सा मॉडल से सामाजिक मॉडल की ओर एक संक्रमण को दर्शाती है।

### भारत में दवियांगता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- **समता और गरमा का मूल अधिकार:** भारत के संवधान के भाग III के तहत गारंटीकृत सभी मूल अधिकारों के पीछे व्यक्तियों की समानता और गरमा एक मौलिक धारणा है, जो दवियांगजनों के अधिकारों की भी रक्षा करती है।
- **राज्य नीति के नदिशक सिद्धांत:** भारत के संवधान के अनुच्छेद 41 में घोषणा की गई है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
  - अनुच्छेद 46 राज्य के लिये यह दायित्व निर्धारित करता है कि वह कमज़ोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
- **वधायी शक्ति:** भारतीय संवधान ने [केंद्र और राज्यों के बीच वधायी शक्तियों](#) का वितरण करते हुए दवियांगता के वधिय को राज्य सूची में रखा है।

### भारत में दवियांगजनों को कनि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- **चहिनति नहीं करना, विकास से वंचित करना:** भारत में दवियांगता को चहिनति करने की जटिलता न केवल हमें मानव विकास के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर पीछे रखती है, बल्कि किसी व्यक्तिको स्वास्थ्य देखभाल एवं कल्याण तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये न्यायपालिका और नौकरशाही तक पहुँच सकने से अवरुद्ध भी करती है।
  - इसके साथ ही, प्रमाणीकरण की एक परत दवियांगजनों (PWD), विशेष रूप से मानसिक दवियांगजनों को कल्याण के गलियारों तक पहुँचने से वंचित कर देती है क्योंकि उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाता है।

- **अवसरचरणात्मक पहुँच का अभाव:** दवियांगजनों द्वारा स्वच्छता, सीढ़ी, रैंप, कैंटीन एवं मनोरंजन कक्ष, अलग वॉश रूम, उद्यान क्षेत्र जैसे बुनियादी ढाँचों के अभाव का सामना करना पड़ता है।
  - इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा प्रतभाशाली दवियांगजनों को रोजगार अवसरों से वंचित रहना पड़ता है क्योंकि रोजगार के अवसर प्रायः शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन्हें कभी-कभी नौकरी छोड़नी भी पड़ती है क्योंकि परिवहन सुविधाएँ उपयुक्त नहीं होती हैं।
    - **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दवियांगता अधिक मौजूद है।
- **समानुभूत के बजाय सहानुभूत का व्यवहार:** सहायता/सहकर्मियों और शिकषकों की असंवेदनशीलता, समावेशी शिकषा तक पहुँच, अधिकारों का संस्थानीकरण आदि कुछ प्रमुख चिंताएँ हैं जो प्रायः दवियांग उम्मीदवारों द्वारा व्यक्त की जाती हैं, जिन्हें किसी तरह स्वीकार तो किया जाता है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। नतीजतन, दवियांगजनों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **समयबद्ध सर्वेक्षण का अभाव और नीति विलिंबन:** **वकिलांग जन अधिकार अधिनियम, 2016** दवियांग बच्चों की पहचान करने, उनकी विशेष ज़रूरतों और उनकी प्रती की स्थिति का पता लगाने के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष पर स्कूल जाने वाले बच्चों के सर्वेक्षण का प्रावधान करता है।
  - लेकिन चूँकि प्राथमिक सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है, इसलिये अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्माण अभी भी पाइपलाइन में है।
- **समावेशी शिकषा का अभाव:** कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई दवियांग बच्चों को महामारी के प्रकोप का सामना करना पड़ा। जनभागीदारी शून्य होने के कारण, उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिये स्क्राइब, सांकेतिक भाषा के दुभाषिए आदि खोजने में संघर्ष करना पड़ा।
  - भले ही स्कूली पाठ्यक्रम को त्वरित रूप से ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया था, समावेशी शिकषा को हानि उठानी पड़ी। इसने मौजूदा समस्याओं को और कष्टजनक बनाया।
- **रोजगार सुरक्षा का अभाव:** बेरोजगारी प्रमुख कारणों में से एक है क्योंकि ऐसे प्रतिकूल समय में दवियांगजन नौकरी से निकाल दिए जाने के लिये सबसे पहले बर्ला का बकरा बनाए जाते हैं।
  - कंपनियों द्वारा लागत में कटौती के तरीके अपनाए जाने पर सबसे पहले उन्हें ही उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाता है।

## आगे की राह

- **बजट नरिमाण और योजना में पारदर्शिता:** दवियांगता प्रतिक्रिया योजना (Disability Response Planning) सभी मंत्रालयों के बजट का अंग हो।
  - तदनुसार, शासन का नीतिगत प्रतमिन वंचित प्रस्थितियों में रह रहे लोगों की आवश्यकताओं की प्रती करने और उन्हें विकास के हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने की दशा में सक्रिय हो।
- **भारतीय सांकेतिक भाषा को चहिनति करना:** ऐसे सभी आधिकारिक संचार में ISL (Indian Sign Language) दुभाषिए को अनविर्य कया जाना चाहिये जहाँ दवियांग संलग्न हों।
  - इसके अलावा, भौतिक डिज़ाइन के साथ-साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में दवियांगों के लिये सुलभ कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **अधगिम के लिये सार्वभौमिक डिज़ाइन:** स्कूलों में पाठ के योजना नरिमाण और उसके वतितरण में बच्चे के तंत्रिका-मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक प्रोफाइल आदि सभी स्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।
  - **युनेसको** ने दवियांग शिकषार्थियों पर कोविड-19 के प्रभाव को समझने के संबंध में अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि:
    - 'अधगिम के लिये सार्वभौमिक डिज़ाइन' (Universal Design for Learning) दृष्टिकोण का उपयोग इन स्थितियों को संबोधित करने, अधगिम सामग्री वकिसति करने और दूरस्थ शिकषा की समावेशिता को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है।
- **सामाजिक दवियांगता से निपटना:** दवियांगता को समाज में एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। निःशक्तता और कुछ नहीं बल्कि अंगों से कषीण होने के बजाय लोगों के मन की अक्षमता है।
  - समस्या तब उत्पन्न होती है जब समाज दवियांगजनों को एक दायित्व या 'चैरिटी' के एक मामले के रूप में देखता है।
  - 'स्पेशल कडिस' शब्द की पूरी अवधारणा ही त्रुटिपूर्ण है। कोई भी दवियांग व्यक्त असाधारण रूप से व्यवहार कये जाने की इच्छा नहीं रखता है। हमें बस उनकी बुनियादी ज़रूरतों के प्रत संवेदनशीलता के नरिमाण की आवश्यकता है।
  - इस प्रकार, उनके अधिकार को एक अनविर्य कदम के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये न कि वह दूसरों की सद्भावना पर नरिभर हो।
- **एक पार-वषियक दृष्टिकोण (Transdisciplinary Approach) अपनाना:** हमें विभिन्न स्तरों पर जागरूकता और क्षमता नरिमाण करने की आवश्यकता है।
  - पारविरिक स्तर पर जागरूकता, सामुदायिक स्तर पर संवेदनशीलता और सरकारी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं एवं पेशेवरों के स्तर पर क्षमता की आवश्यकता है।
    - भारत पोलियो और कृषु से लड़ने में सक्षम हुआ क्योंकि हमने ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाया। दवियांगता से संबद्ध कलंक को मटाने के लिये भी इसी तरह के एक 'ट्रांसडिसिप्लिनरी मॉडल' की आवश्यकता है।

**अभ्यास प्रश्न:** चर्चा करें कि दवियांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने भारत में दवियांगता से संबद्ध कलंक को मटाने में कसि हद तक योगदान किया है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. भारत लाखों वकिलांग व्यक्तियों का घर है। कानून के तहत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध है? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उम्र तक मुफ्त स्कूली शिक्षा ।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिए भूमिका अधिमान्य आवंटन ।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1  
(B) केवल 2 और 3  
(C) केवल 1 और 3  
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/destigmatising-disability>

